"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2004—फाल्गुन 1, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक ई 1-16/2003/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्र. 14015/21/2002-एआईएस (1)-बी, दिनांक 16 जनवरी 2004 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक (3)	भा. प्र. से. के संवर्गीय पद पर वर्तमान पदस्थापना (4)
1.	श्री बृजभूषण लाल तिवारी	16-1-2004	सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
2.	श्री अमीर अली	16-1-2004	अपर कलेक्टर, दुर्ग
3.	श्री भानुप्रताप सिंह नेताम	16-1-2004	संचालक, लोक शिक्षण एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा प[illegible]न उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग.
4.	श्री मुनीश कुमार त्यागी	16-1-2004	मुख्य सचिव के उप सचिव
5.	श्री गेंद सिंह धनंजय	16-1-2004	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक बी-1-44/2003/4/एक.—श्री चन्द्रकांत उइके, (आरआर-95 रा.प्र.से. वरिष्ठ श्रेणी) आयुक्त, नगर निगम, दुर्ग की सेवायें नगरीय [illegible] विभाग से वापिस लेते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के प[illegible]र पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक बी-1-29/2002/4/एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-1-2004 की कंडिका-1 के अनुक्रम में श्री जे. मिंज (आर आर-81, रा.प्र.से. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी) को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक बी-1-29/2002/4/एक.—श्री जे. मिंज (आरआर-81, रा.प्र.से. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी) अपर कलेक्टर, रायपुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आर. जी. के. पिल्लई, (आर आर-84, रा. प्र से. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी) अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की सेवायें तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर नियुक्ति हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती हैं.

3. श्री टी. के. वर्मा, (आर आर-93, रा. प्र. से. वरिष्ठ श्रेणी) संयुक्त कलेक्टर, राजनांदगांव की सेवायें तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम के पद पर नियुक्ति हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती हैं.

4. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 26-9-2003 के सरल क्रमांक-1 जो श्री राजकुमार टंडन (आरआर-89, रा.प्र.से. प्रवर श्रेणी) अतिरिक्त संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम पदस्थ करने संबंधी है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

5. इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-1-41/2003/4/एक दिनांक 18-11-2003, जिसके द्वारा श्री एम. एस. परस्ते (आरआर-83/87, रा.प्र.से. प्रवर श्रेणी) स्थानापन्न उप सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को अपर कलेक्टर, नारायणपुर जिला बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया था, तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 15-12-2003 द्वारा आगामी आदेश तक, उक्त आदेश स्थगित रखा गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. श्री परस्ते, उप सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के पद पर यथावत् बने रहेंगे.

6. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 26-9-2003 के सरल क्रमांक-3 जो श्री एन. के. शुक्ला (आरआर-89, रा.प्र.से. प्रवर श्रेणी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को उप सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग पदस्थ करने संबंधी है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2004

क्रमांक एफ 10-6/2002/1/5.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 390/2001/1/5/374, दिनांक 21 सितम्बर, 2001 द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित आर्थिक सलाहकार परिषद् को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2004

क्रमांक 322/76/2004/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर उत्तर वस्तर कांकेर को दिनांक 14-1-2004 से 16-1-2004 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18-1-2004 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. ध्रुव, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. एन. ध्रुव, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. ध्रुव, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक 92/2040/32/02.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 192/2040/आपर्या/32/02 दिनांक 22-9-2003 द्वारा ग्राम रिसदा विकास योजना कोरबा में उपान्तरण प्रस्तावित किये गये हैं जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम रिसदा कोरबा के खसरा क्रमांक 615/1 का भाग रकबा 10.47 हेक्टेयर तथा भाग क्रमांक 716/1 का भाग रकबा 8.32 हेक्टेयर कुल रकबा 18.79 हेक्टेयर की सूचना में किए गये उल्लेख अनुसार विकास योजना कोरबा में निर्धारित उपयोग वृक्षारोपण से आवासीय में उपान्तरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करती है कि यह उपान्तरण ग्राम रिसदा कोरबा विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 1-8/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री अशोक शर्मा, पूर्व सांसद, राजनांदगांव को, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रायपुर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 1-8/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-18/खाद्य/2001/29, दिनांक 23 मार्च, 2001 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रायपुर के संचालक मंडल में निम्नांकित अशासकीय सदस्यों को संचालक के रूप में मनोनयन करता है.

स. क्र. (1)	अशासकीय सदस्य का नाम (2)	पद (3)
1.	श्री संजीव शाह	संचालक
2.	कु. पिंकी ध्रुव	संचालक
3.	श्री बद्रीधर दीवान	संचालक
4.	श्री विजय अग्रवाल	संचालक

2. चार शासकीय संचालक पूर्वानुसार ही रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-24/02/(6) 52.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-1-24/(6) 52, दिनांक 23-1-04 के सरल क्रमांक-8 में योग के कालम में अंकित राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख) के स्थान पर रु. 50,000/- (पचास हजार) पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक 119/जेल/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रिजन एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ में स्थित उप जेल भवन को जेल घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक 122/जेल/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 119 दिनांक 4-2-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th February 2004

No. 119/Jail/2004.—In exercise of the powers conferred by Prisons Act, 1894, under section 3 (1) the State Government declares the building of Sub Jail, Manendragarh, District Koriya, Chhattisgarh a Jail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DIVEDI, Joint Secretary.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक एफ-73-39/03/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत एम. एन. आर. एण्ड ए. एस. आर. के. यूनिवर्सिटी, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उप नियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है तथा उप नियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 22 (बाईस) प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

MNR & ASRK UNIVERSITY

Established under section 5 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002, vide Notification of the Government of Chattisgarh.

FIRST STATUTES

In accordance with the provisions section 25 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyala (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002

1. **Short title, Extent and Commencement**

a) These Statutes shall, here - in - after called, The FIRST STATUTES of the MNR & ASRK UNIVERSITY, 2003.

b) The First Statutes are applicable to MNR & ASRK University and any matter relating to or and incidental there to.

c) The First Statutes shall come into force on the date of publication of the First Statutes by the Government of Chattisgarh in the Official Gazette.

d) The Registered office of the MNR & ASRK University shall be situated at Raipur.

2. **Definitions**

In these First Statutes, unless and other wise the context demands:

a) Act means, the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002.

b) Academic Year means the period from June 1 of any year to May 31 of the following year :

c) Ad - hoc committee means a committee constituted under the Section 16.0 of these First Statutes.

d) Affiliation means and includes recognition of colleges, association of colleges located in or outside Chattisgarh, and admission of such colleges under the University for the purpose of conducting the educational and professional programs of the University.

e) Authorities mean authorities mentioned under section 19 of the Act, Section 11 of these First Statutes.

f) Academic Council means the Academic Council constituted under section 22 of the Act and under Section 11.0 of these First Statutes.

g) **Board** means the Board of Management of the University constituted under Section 21 of the Act and Section 10.0 of these First Statutes.

h) Chancellor means the Chancellor of the University as mentioned in section 14 of the Act and Section 5.0 of these First Statutes.

i) Committee means all committees constituted under Sections 12, 13, 14, 15, 16 and 17 of these First Statutes.

j) Common Seal means the authoritative seal of the University established under section 6 of the Act.

k) Course includes programs and courses of studies imparted in the classroom framework and also in the distance mode.

l) Distance education includes the education / course / programs provided to students on off campus mode.

m) Fund means the fund established under Section 7 of the Act and Section 10.4 of these First Statutes.

n) Financial year means the period commencing on the 1st April of any year and ending with 31st March of the following year.

o) Finance Committee means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 14.0 of these First Statutes.

p) Government means the Government of the State of Chattisgarh.

q) He includes She and His includes Her:

r) Institute means any institute constituted as part of the University to deal in different disciplines, located within or outside the state of Chattisgarh.

s) Manual of Instructions Includes all rule, procedures, instructions and systems laid down by various committees, Boards, authorities, officers of the University for the purpose of smoothly conducting the business of the University.

t) Ordinance means ordinance issued by the University as prescribes by Section 27 of the Act.

u) Rules mean the Rules made under Section 36 of the Act.

v) Regulations mean Regulations made under Section 37 of the Act.

w) States means the States of India formulated under the relevant legislation of the Parliament.

x) Statutes means the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications of the Statutes.

y) Sponsor means the MNR & VNR Educationl Society registered at Raipur, Chattisgarh under the provisions of Chattisgarh Panjikaran Adhiniyam.

z) Student means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University.

aa) Staff means the teaching and non - teaching employees of the University who are on direct permanent payroll of the University and does not include any casual, temporary, contractual, ad-hoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or task:

bb) University means the MNR & ASRK University established under section 5 of the Act and will have the same meaning as stated in the University Grants Commission Act, 1956;

cc) Vice-Chancellor means the Vice-chancellor of the University appointed within the meaning of section 15 of the Act and Section 6.0 of these First Statutes.

dd) Visitor means the Visitor as defined under section 13 of the Act and Section 4.0 of these First Statutes.

Object of the University

The main objects of the University are as follows:

a) To provide instruction, teaching and training in the field of higher education; and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge.

b) To establish a campus in the State of Chattisgarh and to have affiliate instructions study centers at different places in India and other countries.

c) To create higher levels of intellectual abilities1

d) To establish state of the art facilities for education, training and research;

e) To offer continuing and distance education programs;

f) To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any other method of evaluation;

g) To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are high standard.

h) To encourage and promote research activities and set up independent research institutions for pure and applied research, and institute awards and fellowships at institutions other than the University for undertaking research.

i) To affiliate or collaborate with any other college or University, research institution, industry association, professional association or any other organization, in India of overseas, to conceptualize, design and develop specific educational and research programs, training programs and exchange programs for students, faculty members and others.

j) To undertake surveys, studies and consultancy for any organization in India or overseas.

k) To disseminate knowledge through seminars, conferences, executive education programs, community development programs, publications, and training programs.

l) To undertake programs for the training and development of faculty members of the University and other institutions in India or overseas.

m) To undertake collaborative research with any organization in India or overseas, and undertake commercialization of technologies.

n) To develop, register and licence all forms of intellectual property rights, including, interalia, trademarks, copyrights, know-how and patents, etc.

o) To conceptualize, design, develop and commercialize various products, equipment and machinery as part of the research and development activity.

p) To encourage sports, cultural, and extra curricular and co-curricular activities for students and staff.

q) To do all things necessary or expedient to promote the above objectives.

r) To pursue any other objective as may be approved by the Board;

4. Powers of the "Visitor" of University

a) The Governor of Chattisgarh shall be the "Visitor" of the University.

b) The visitor shall present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.

c) The visitor can call for any paper or information relating to the affairs of the University.

d) Based on the information received by the visitor, if he is satisfied that any order, proceeding or decision taken by any authority of the University is not is conformity with the Adhiniyam, Regulations, Ordinances or Rules, he may issue such directions as he may deem fit is the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all the concerned.

e) With the prior approval of the visitor, the chancellor shall be appointed.

5. Appoint and power of the Chancellor.

a) The Chancellor shall be appointed by the Sponsor with the prior approval of the Visitor.

b) The term of office of the Chancellor shall be three years, and he may be reappointed for successive terms, at the pleasure of the Sponsor.

c) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and the head of the University.

d) The Chancellor shall obtain Ratification from the Governing Body on the decision taken by him

e) The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the Visitor is not present.

f) The Chancellor shall have the following powers:
   i) To call for any information on record.
   ii) To appoint the Vice-chancellor.
   iii) To remove the Vice-chancellor.
   iv) Such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

g) In the opinion of the Sponsor, the actions of the Chancellor are found to be in any way detrimental to the interests of the University, the Sponsor shall appoint such other person as may be found appropriate in the position of Chancellor to succeed the person so acting. Provided that, the Sponsor shall seek the prior approval of the visitor before appointing such other person as the Chancellor. The Sponsor may stipulate the date from which such other person shall assume the office of the Chancellor.

g) The General Body may from time to time decide on the Honorarium and / or the pay and or allowances to be paid to the Chancellor and / or perquisites to be provided to the Chancellor.

h) The office of the Chancellor may be located any where in India or overseas.

6. **Appointment powers and responsibilities of the Vice - Chancellor**

a) The Vice - Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body.

b) The term of office of the Vice - Chancellor shall initially be Four years, and he may be reappointed for successive term(s) by the Chancellor.

c) The Vice - Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and also the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and other Committees that may be set up by the Governing Body or the Board from time to time.

d) The Vice - Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University, and shall exercise such powers and perform such duties as ma be prescribed by the Act and the Statutes.

e) In absence of the Chancellor, the Vice-chancellor shall undertake all the functions of the Chancellor. and shall preside over the Convocation in th^ absence of the Chancellor.

f). If in the opinion of the Vice - Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision there on shall be final.

Provide further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-chancellor.

g) If in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by the Act, Statutes or Ordinances or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority revise its decision within seven day from the date of his decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

h) If at any time upon representation being made of otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor by an order in writing stating the reasons therein, may ask the Vice - Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

7. **Appoint, powers and responsibilities of the Registrar**

a) the Registrar shall be appointed by the Vice - Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

b) The selection committee shall consist of the following members:

i. Vice – Chancellor
ii. One representative of the Chancellor.
iii. Two representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body,
iv. One expert nominated by the Board of Management, who is not in any way connected with the University.

c) The term of office of the Registrar shall be as mention in the order of his appointment by the Vice - Chancellor.

d) The Registrar shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

e) The Registrar shall draw such emoluments, which shall not be less than the emoluments of Professor or equivalent person as prescribed by the UGC from time to time.

f) The Registrar shall undertake such functions as may be specified by the Governing Body or the Board of Management or the Vice - Chancellor.

g) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Board of Management, the Academic Council and such other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act or the Statutes or the Ordinances.

h) The Registrar shall report to the Vice - Chancellor.

(i) The following shall be the duties of the Registrar :

i) To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University and the Governing Body or the Boardd, shall commit to his charge.

ii) To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

iii) To collect all income and disburse the same for the purposes of the University as sanctioned by the vice - Chancellor.

iv) To make Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities with the approval of the vice-Chancellor.

v) To keep the minutes of the meetings of all the authorities of the University and of all the committees and sub-Committees appointed by any of these authorities and circulate the same among themembers, with the approval of the Vice- Chancellor.

vi) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his representatives for this purpose.

vii) To enter into agreements, contrct on behalf of the University and make amendments and alterations in the terms of such agreements or contracts as may be directed by the Board.

viii) To sign documents reports and documents to the government and conduct liason with the State Government, Central Government, University Grants Commission and other Government authorities.

ix) To generally supervise the administration function at the University.

x) To supervise and manage the conduct of the Examinations of the University, subject to control of the Vice-Chancellor.

xi) To perform suchother duties as may be specified by the Board of Management or the Vice-Chancellor from time to time.

8. Appointment, powers and responsibilities of the Chief Finance & Accounts Officer.

a) The Chief Finance & Accounts Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose with prior approval of Chancellor.

b) The selection committee shall consist of:
   i) The Vice Chancellor
   ii) The Registrar.
   iii) One representative of the Chancellor.
   iv) One representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body.
   v). One expert nominated by the Board of Management who is not in any way connected with the University.

c) The Chief Finance & Accounts Officer shall have such qualifications and the Governing Body may prescribe experience as from time to time.

d) The Chief Finance & Accounts Officer shall draw such salary, allowances and entitled such perquisites which shall not be less than the emoluments of the Deputy Registrar or equivalent person as prescribed by the UGC from time to time.

e) the term of office and the terms of appointment of the Chief Finance Officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice - Chancellor.

f) The Vice - Chancellor may appoint a person to officiate as the Chief Finance Officer in the event of temporary absence of the Chief Finance and Accounts Officer.

g) The Chief Finance & Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University and shall have such powers and responsibilities as may be delegated or the Finance Committee or the Vice - Chancellor of the Registrar.

h) The Chief Finance & Accounts Officer shall report to the Registrar.

9.0 The Governing Body

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

9.1 Constitution of the Governing Body

The Governing Body shall consist of the following members:
(i) The Chancellor.
(ii) The Vice - Chancellor.
(iii) Three persons nominated by the Sponsor.
(iv) One nominee of the Government.
(v) One educationist of repute to be nominated by the Government.
(vi) One academician to be nominated by the visitor.

9.2 Term of the Governing Body

a). The members of the Governing Body shall have a term of 3 years.

b). If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

9.3 Disqualifications of the Members of the Governing Body

The members of the Governing Body shall cease to members under the following circumstances.

(i) If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

(ii) If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

9.4 Powers of the Governing Body

a) The Governing Body shall have the following powers:

(i) To appoint Auditors of the University.

(ii) To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances:

(iii) To approve the annual report and Accounts of the University.

(iv) To lay down policies to be followed by the University

(v) To take decision about the voluntary liquidation of the University.

(vi). To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

b) The Governing Body shall perform such other functions as it may deem necessary for proper functioning and administration of the University.

9.5 Reserve Powers of Governing Body

a) In case of any deadlock of Management and operations of the University cannot be conducted in the normal course, reserve powers are vested with Governing Body to do all necessary things including superceding the Board and forming a new Board to facilitate smooth functioning of the University.

b) The reserve powers of the Governing Body shall be exercised only when there is a written report sent by the Register to the Chancellor of the Vice-Chancellor about the deadlock in the Board and when the operations of the University cannot be conducted in the normal course.

c) Upon receipt of such a written report, the Chancellor of the Vice-Chancellor shall direct the Registrar to convene a special meeting of the Board within 15 days for restoration of normalcy in operations. In the event of Registrar not convening such a special meeting, the Chancellor shall convene such a meeting.

d) The decisions taken by the Governing Body and implemented by the officers under this clause shall be final and binding on all the Members of the Board and on all the Members of the Governing Body.

9.6 Meetings of the Governing Body

a) The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the university or any other location as may be agreed by majority of the members.

b) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body in absence of the Chancellor, the Vice-chancellor shall preside over the meeting.

c) A notice of 21 days shall be given to the members stating the agenda for meeting. A notice less than 21 days may be considered sufficient if majority of the members agree to such a shorter notice.

d) The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

e) Each member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority case of a tie, the presiding officer shall a casting vote.

The presiding officer of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of one month from the date of such meeting.

9.7 Extraordinary meeting of the Governing Body

a) In the event of exigency, the Chancellor or the Vice - Chancellor with the concurrence of the Chancellor ma call for the extraordinary general meeting of the Governing Body.

b) The Sponsor may, in the event of exigency and / or in the interest of the administration of University, request the Chancellor, or in his absence, the Vice - Chancellor either to call for an extraordinary meeting or circulate he resolution among the members of the Governing Body.

c) The Chancellor or the Vice - Chancellor with the concurrence of the Chancellor, may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

10.0 The Board of Management

The Board of Management shall be the principal executive body of the University

10.1 Constitution of the Board of Management

a) Following members shall constitute the Board:
   (i) The Vice - Chancellor.
   (ii) The Registrar.
   (iii) One representative to be nominated by the State Government.
   (iv) Senior most Professor of the University to be nominated by the Chancellor.
   (v) Two representatives to be nominated by the Sponsor.

b). The Vice - chancellor shall be the Chairman of the Board and the Registrar shall be the Member Secretary.

c) The Vice - chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice - Chancellor, the Registrar shall conduct the proceedings of the meeting.

d). The tenure of the members of Board of Management shall be three years, except in the case of Ex-officio members.

10.2 Disqualification of the Members of the Board

The members of the Board of Management shall cease to members under the following circumstances.

(i) If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

(ii) If in the opinion of the Chancellor, a member of the Board acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such as may be specified.

10.3 Meetings of the Board

a). The board of the management shall meet as often as necessary, and at least once in three months.

b) The meetings shall be called by the Registrar.

c). A notice of 7 days shall be given for the meeting, provided that an emergency meeting may be convened, at the discretion of the Vice - Chancellor, at a short notice.

d) The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

e) Each member of the Board including the Chairman / Presiding Officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be taken by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall exercise a casting vote.

f). The Registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice - Chancellor and circulate them to the members concerned within a period of one month from the date of conducting of the meeting.

g) the Vice - Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Board by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.

10.4 Powers of Board of Management

The Board of Management shall have the powers to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The powers shall, interalia, include but not limited to, the following:

A) Financial Matters

a) To consider the budget as recommended by the Finance Committee and to approve the same with or without modifications, by the Governing Body.

b) To manage and administer the revenues and properties of the University and to conclude all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

c) To manage and regulate the finance, accounts, investments, properly and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agent or agents as it may deem fit.

d) To open account or accounts of the University with any one or more scheduled banks and to lay - down the procedure for operating the same.

e) To draw, accept, make, endorse, discount and negotiate securities of the Government, promissory notes, bills and exchange, cheques or other negotiable instruments.

f) To issue appeals for funds for carrying out the objects of the University.

g) To receive grants, donations, contributions, gifts, prizes scholarships, fees and other moneys; and to give grants and donations, to award prizes, scholarships etc.

h) To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or buildings or works which may be necessary or convenient for the purposes of the University, and, on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works.
To acquire intellectual property rights, copy rights, trade marks and the like from any institution or organization, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

j) To transfer or accept transfers of any moveable property on behalf of the University.

k) To execute in consultation with the Holding Trustees (if any) / Sponsor, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases, bonds licenses and agreements in respect of property moveable or immovable belonging to the University or to be acquired for the purposes of the University.

l) To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit.

m) To invest the funds of the University or money entrusted to the University, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment.

n) In consultation with Holding Trustees (if any) Sponsor, to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities by providing properties and assets of the University as security, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all expenses, incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

o) To maintain and operate the General Fund as stipulated in Section 20.0 of these Fist Statutes.

p) To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance - Sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations and submit the same to the Governing Body for their approval.

B) Appointments

a) To create teaching and academic posts and to decide on the number, qualifications and cadres thereof, and to determine the emoluments of such posts.

b) To appoint Directors, Principals, Deans, Professors, Associate Professors and other senior academic and operational staff, as may be necessary.

c) To lay down rules with respect to emoluments and duties for the various academic and non - academic staff recruited by the University.

d) To lay down rules for appointment of Visiting Fellows and Visiting Professors and their emoluments.

e) To appoint internal auditors to undertake audit of the various functions of the University.

C) Academic Matters

a) To generally lay down, in consultation with the Academic Council, the academic policies, education and teaching standards and policies relating to student admission, examinations and award of degrees, diplomas and certificates and other academic awards of distinctions.

b) To establish, on the advice of the Academic Council, Divisions and Departments for the academic work and functions of the University and to allocate areas of Study, Teaching and Research to them.

c) To lay down policy relation to bees and other charges payable by the students of the University.

d) To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the regulations.

e) To lay down rules regarding the emoluments and traveling and other allowances of examiners, moderators, tabulators and such other personnel appointed for examinations, in consultation with the Academic Council and the Finance Committee.

D. Student Matters and Discipline

a) To regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and to take appropriate disciplinarian action wherever necessary.

b) To entertain and adjudicate upon any grievance of the employees and students of the University; and to set up committees for attending to such grievances.

c) To establish and regulate the maintenance of hostels for the students of the University and recognize hostels established by outside parties, on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

E) Administrative and Legal Matters

a) To approve contracts and works.

b) To create administrative, ministerial and other necessary posts and fix compensation for persons recruited to such posts.

c) To grant leave of absence to the Vice - Chancellor or any other officer of the University and to make necessary arrangements to carry out the function of such officers preceeding on leave during their absence.

d) To conduct inspections and enquires, in various department, centers, institutions and affiliate colleges of the University and initiate corrective action wherever needed.

E) Formation of Sub - Committees

The Board of Management may form sub - Committees and / or Ad - Hoc committees for discharging any of the functions of the Board, by clearly specifying their scope, jurisdiction, authority, powers and functions.

10.5 Delegation of Powers

The Board Of Management may by a resolution, delegate to the Vice - Chancellor, Registrar, Standing Committee or the Ad - hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice - Chancellor or the Standing Committees or the Ad - hoc Committee, or any of their Officers to whom such powers are delegated, shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

11.0 The Academic Council

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Regulations and shall have the control over and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching and training, inter - departmental co-ordination, research, examinations and tests within the University.

11.1 Constitution of the Academic Council

a) The Academic Council shall consist of the following members:

i) The Vice - Chancellor.

ii) The Registrar.

iii) Five Heads of various institutions under the University to be nominated by the Chancellor.

iv) Five faculty members designated as professors and drawing pay of professors as prescribed by the UGC to be nominated by the Chancellor.

v) Five outside experts nominated by the Chancellor.

b) The Vice - Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

c) The term of members of the Academic Council shall be three years, except in the case of the employees of the University who are members of the Academic Council. The term of such members who are employees ends immediately after their relinquishing their office at the University.

d) Subject to the provisions of the Act, Statutes and the Regulations the Academic council shall have the power to control, regulate and maintain the standards of education, instruction and examinations of the University and shall exercise such other powers and functions as may be conferred or imposed upon it by this Act, Statutes of the Board.

e) The Vice - Chancellor may invite such other persons, as he may deem fit, to attend the meetings of the Academic Council from time to time. However, such persons invited shall not be eligible to vote on any of the resolutions of the Academic Council.

11.2 Disqualification of the Members of the Academic Council

a) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when the ceases to hold that office or appointment.

b) A member of the Academic Council shall cease to be a member in the following circumstances:
   i) If the Member resigns from the Academic Council.
   ii) If the Member had been convicted of a criminal offence involving moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.
   iii) If the Member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council, without leave of the Chairman.

11.3 Meetings of the Academic Council

a) The Academic Council shall meet as often as may be necessary.
b) One third of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.
c) Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation of such Resolutions among all the members, except in cases where such Resolutions are required to be passed at a meeting convened. The resolution so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such Resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

11.4 Functions and Powers of the Academic Council

Subject to the provisions of the Act Statutes and the Ordinances, the powers of the Academic Council shall include, interalia, the following:

a) To report and act on any matter referred or delegated to it by the Board.

b) To formulate different courses and programs to be imparted to the students of the University.

c) To lay down the curriculum and frame syllabus for any of the courses and programs offered by the University, and publish text books and other instruction material for the same.

d) To make recommendations to the Board, with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments and the duties attached thereto.

e) To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Board as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another.

f) To make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University.

g) To promote research activities and programs, and to ask for, from time to time, reports on such research activities and programs.

h) To consider proposals submitted by the faculties relating to instruction, teaching facilities, etc.

i) To appoint committees for admission of students to the University.

j) To recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University on reciprocal basis:

k) To approve conferment of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour on the basis of the results declared;

l) To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarships, medals and prizes, etc, and empower the Vice - Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

m). To prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and to perform in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of provisons of the Act and / or the regulations.

n) To make recommendations to the Board of Management on:
(i) Measures for improving of standards of teaching, training and research and examinations.
(ii) Institution of Fellowships, Exchange Programs, Scholarships, Medals, Prizes etc.
(iii) Regulations covering the academic functioning of the institute, discipline, residence, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free ships, concessions, attendance etc and submit the same to the Board of Management for approval.

o) To suggest measures for departmental co-ordination.

p) To appoint committees, consisting of such members as the Academic Council may deem fit, to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

12.0 Examination Committee

1) The Vice - Chancellor shall constitute Examinations Committee with respect to each faculty, for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners for various examinations and for suggesting evaluation methods for each subject of the faculty.

2) The Examinations Committee shall consist of;
i) The Dean of the Faculty, Chairman.
ii) Professor of the subject.
iii) One expert in the subject nominated by the Vice-Chancellor.
iv) Registrar

3. The examination committee shall recommend a panel of examiners for each subject of the courses of study to the Vice - Chancellor.

4. The Vice - Chancellor shall ordinarily appoint examiners from the panel recommended by the examinations committee, provided that with the approval of the Chancellor he may appoint examiners outside the panel, if he deems fit and necessary.

13.0 Results Committee

a) The Vice - Chancellor shall constitute a Results Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

b). The Results Committee shall consi of:
- i). Dean of the faculty concerne
- ii). One professor of the subjects assigned to the faculty.
- iii). One expert nominated by the Chancellor.
- iv). The Registrar.

c). If in the opinion of the Results Co mittee the result of any examination is not properly balanced or evaluation of any paper is not properly balanced, the Results Committee may recommend action to be taken by the Vice - Chancellor.

14. 0 The Finance Committee and its Constitution

a) The Governing body may appoint Finance Committee.

b) The Finance Committee shall consist of the following members namely:
- i) The Vice - Chancellor.
- ii) The Registrar.
- iii) The Chief Finance and Accounts Officer.
- iv) Two nominees of the Sponsor who are members of the Governing Body.

c. The Vice - Chancellor shall be the Chairman of the Committee and in his absence the Registrar shall preside over the meetings of the committee.

14.1 Meetings of the Finance Committee

a) The committee shall meet as ofte as necessary.

b) the quorum of the meetings shall be one third of the members of the committee.

c) The Registrar shall call the mee ng of the Finance Committee with approval of the Vice Chancellor.

d) A notice of 7 days shall be given to its members stating the agenda, time and place of the meeting, provided that an emergency meeting can be called by the Vice Chancellor at a shorter notice.

e). The Registrar shall cause recording of the minutes and resolutions of the meeting and circulate the same with the approval of the Vice - Chancellor.

14.2 Powers and Functions of the Finance Committee

a). To make recommendation of all financial matters to the Board.

b) To consider all proposals for capital expenditure and to make recommendations to the Board.

c) To examine the annual accounts of the University and advise the Board.

d) To examine the annual budget estimate and advise the Board thereon.

e). To review the financial position of the University from time to time recommend any action to be taken to the Board.

f) To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

g) To make recommendations to the Board on all proposals involving the raising of funds, receipts and expenditure.

h) To determine and fix the fee payable by the students of the University and lay down the procedure therefore and to fix the basis for charging consultancy and other fee to be charged by the University.

i). To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Vice - Chancellor or the Board or the Governing Body.

15.0 Selection Committee

a) The Board may appoint a selection committee to recommend names of the persons to the posts of Professors. Associate Professors, Assistant Professors, and such other academic posts as may be prescribed by the Board of Management.

b) The selection committee so appointed shall consist of:

i) The Vice – Chancellor.
ii) Three experts in the relevant disciplines nominated by the Chancellor.
iii) One Nominee ~~from the Board of Management~~ nominated by the sponsor
iv) Dean of the faculty.

16.0 Constitution of Standing Committees and Ad-hoc Committees

a) The Governing Body and/or the Board of Management may, at the appropriate time, by a resolution in a duly conducted meeting, and or in accordance with the directions of the Chancellor, appoint standing committees or ad-hoc committees, and / or enquiry committees by defining

i) The purpose of appointment
ii) The constitution
iii) The tenure of the committee
iv) The financial budget
v) The procedure to be adopted
vi) The rights and obligations of the committee
vii) The remuneration payable to the members of the committee

viii) The facilities to be acquired and

ix) Other matters relevant or incidental to complete the purpose for which it is Appointed.

b) The committee so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority.Neither the University nor the Governing Body, nor the Board of the Management shall be accountable for the authority or powers used outside the scope of delegation by such committees.

c) Such committees shall be automatically dissolved on completion of their tenure or After completion of the tasks assigned to them by the authority appointing them, unless extension of delegation is granted by the side authority.

17.0 Advisory Committees

a) The Board may, with the concurrence of the Chancellor, appoint an Advisory Committee consisting of five members for the purpose of providing advice to To the Board in matters relating to the conduct of various affairs of the University.

b) The Board may direct Academic Council, Finance Committee and / or any other Committee set up under the Act or these statutes, to appoint and / or follow the Recommendations of the Advisory Board.

c) The Board may define the functions, and powers while establishing such committees.

18.0 Service Conditions for Faculty members, Officers and other Employees

There shall be following types of appointments.

a) **Contract basis**: Any teaching/ Non-teaching posts whose services are required for short term or for a period of fix tenure, shall be appointed on contract basis. The Board of Management shall decide terms and condition of contract.

b) **Adhoc basis:**To fulfill the immediate requirement of University, the University may appoint any person on adhoc basis for teaching and non-teaching post by the Vice Chancellor. The tenure of the adhoc appointment shall not be more then six months. However in view of the Vice Chancellor the services of the person is required in the interest of the University then he/ she may be reappointed on adhoc basis with the approval of Board of Management. Provided further that in case of clear vacancy the person appointed on the adhoc basis may be considered for the appointment after fulfilling the requirement of regular selection.

c) **Regular basis:** The regular appointment shall be made on the posts created by the University through the properly constituted selection Committee. The Board of Management shall decide pay scales and service condition for non-teaching employees.

d) The teachers shall be recruited through the duly constituted selection committee. The qualifications of the teachers shall be at-par to the UGC norms and the pay scale shall be as per UGC recommendations approved by the State Government and by the University.

19.0 Budgets

a) The Chief Finance and Accounts office, with the approval of the Finance Committee, based on the proposed budgets received from different departments, divisions,colleges institutes of the University, shall prepare an annual budget for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year to the Board, for the purpose of approving the same. The Board upon the merits may suggest modifications, alterations or additions or approve the same with or without modifications and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

b) No expenditure other then that provided in the budget shall be incurred by the depart--ments, divisions, colleges, and institutes of University without the approval of the Finance Committee.

c) The Finance Committee may consider any revision of the Budget, based on the recommendation of the Chief Finance and Accounts Office and on merits, and such revisions shall be placed for rectification of the Board at a subsequent meeting of the Board.

20.0 Accounts and Audit

a) The accounting year of the University shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year.

b) The accounts of the various divisions, departments, institutions and campuses of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts Officer and he shall make out the final annual accounts, consisting of the Income and Expenditure Account and Balance Sheet of the University and place the same before the Finance Committee for their comments. The appropriations of excess income over expenditure or the absorption of excess of expenditure over the income shall be decided by the Finance Committee. The accounts will thereafter be adopted by the Board, which they will be audited by the Auditors appointed by the Governing Body.

c) All the assets of the University shall be maintained in the name of the University and shall be used for the settlement of liabilities at the same time of liquidation or closure of University under sections 33 and 34 of the Act.

d) The accounts of the University shall be open to examinations by the Chancellor, Vice-Chancellor, Registrar, Auditor of the University and any other person authorised by the Governing Body or the sponsor for the purpose.

e) Every balance sheet and income and expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standards as may be prescribed by the Government of India in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards.

f) The Vice-Chancellor shall place such audited financial statements before the Governing Body, along with the report of the Auditors for information.

g) The Registrar, thereafter along with the annual report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and the Government as provided under section 30 of the Act.

21.0 Arbitration in case of disputes

a) The Vice-Chancellor shall be responsible for resolution of disputes and grievances between the teachers, officers and other employees and the students of University.

b) The Vice-Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans of the Faculties as he may deem fit.

c) Any person who is aggrieved of the decision of the Vice-Chancellor may appeal to the Chancellor within 15 days of communication of the decision by Vice-Chancellor.

d) The Chancellor shall form a three members Committee to arbitrate such disputes and grievances. The Committee shall consist of one member nominated by the Vice-Chancellor, one member by the aggrieved person and the chairman of the Committee shall be nominated by the Chancellor who shall not concerned with the University.

e) The decision of arbitration Committee shall be final.

22.0 Interpretation

a) In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the statute Ordinances and the Regulations, the provisions of the Act shall prevail.

b) The decision of the Governing Body on interpretation shall be final and bending.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2003.

क्रमांक एफ-73-70/03/उ.शि./38.--राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत गुरूकुल विश्वविद्यालय, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उप नियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है तथा उप नियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 01 से 14 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

STATUTE No.1

Powers and duties of the Chancellor
(Section 14 (4) of the Adhiniyam)

14. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with prior approval of the Visitor by following such procedure and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chancellor shall be the head of the University.

(3) The Chancellor shall preside at the meeting of the governing body and shall, when the Visitor is not present, preside at the convocation of the University for conferring degrees or diplomas.

(4) The Chancellor shall have the following powers namely,
(a) To call for any information or record.
(b) To appoint the Vice-chancellor.
(c) To remove the Vice-chancellor.
(d) Such other powers as may be prescribed by the statues.

Besides the powers listed in Section 14 (1) to (4) above the Chancellor shall have following powers namely:

1) The Chancellor may appoint an Academician/ and /or Administrator as his Academic Adviser/ Administrative Adviser on payment of a fixed Honorarium, facilities and largesses as he deems fit.

2) The Chancellor may constitute such committees, as he deems necessary to help him in discharge of duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.

3) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body which will be the supreme authority of the University

4) (i) To review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with this Adhiniyam, Rules, Statues or Ordinances.

(ii) To approve the budget and annual report of the University.

(iii) To lay down the extensive policies to be followed by the University.

(iv) To take decision about the voluntary liquidation of the University.

STATUTE No. 2

Terms and conditions of Appointment of Vice-Chancellor His powers and duties

(Section 25(1) (b) read with Section 15 (1) of the Adhiniyam)

1. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommenced by the Governing Body for a term of four years and shall in no case be eligible for reappointment for more than two terms. Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of 70 years Provided further that not withstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters in the office but this period shall not in any case exceed six months.

2. The Vice-Chancellor shall be whole time salaried officer of the University. He will receive salary recommended by University Grants Commission and approved by the State Government from time to time plus other allowances admitted by the Governing body from time to time or as mutually agreed by, the Vice-Chancellor and the Society.

3. During the tenure of office the Vice-Chancellor shall be entitled to have a rent free furnished accommodation maintained by the University.

4. The Vice-Chancellor shall be entitled to use University vehicle

for official purposes. He shall pay such amount for use of the vehicle as may be prescribed by the Government for its vehicles for use by Government officers on monthly basis. The Vice-Chancellor shall also be eligible to use the University vehicle for private purposes and for such journeys he will be liable to pay such charges as are prescribed by Government for private use of Government vehicle by officers on the basis of kilometers involved in private use.

5. The Vice-Chancellor shall be entitled to other benefits such as medical allowances and leave travel concessions as admissible to other University employees.

6. The Vice-Chancellor shall be entitled to Travelling Allowance from place of his residence on his appointment as Vice-Chancellor and after relinquishment of his charge.

7. The Vice-Chancellor shall have power to constitute such committees, as he deems necessary to help him in the discharge of the duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.

8. The Vice-Chancellor shall have power to sanction an allowance to any employee of the University for any special duty assigned to such employee for additional duties performed by him which in the opinion of Vice-Chancellor warrants such payment. Provided that such allowance shall not exceed 20% of the basic salary of such employee. Provided further that any action taken under this clause of Statute shall be reported to Board of Management at its next meeting.

STATUTE No. 3

Terms and conditions of Appointment of Registrar his duties and powers

(Section 25(a) read with section, 16(1) of the Adhiniyam)

1. The Registrar shall receive salary in the pay scale prescribed by University Grants Commission and admitted by the Governing Body from time to time or as mutually agreed by the Registrar & the Society.

2. No person shall be eligible for appointment as Registrar unless he/she possesses the minimum qualification applicable to Professor's post and as the Governing Body may, from time to time.

3. The Registrar shall be fulltime salaried officer of the University.

4. The Registrar shall be entitled to leave, leave salary allowances and other benefits as may be prescribed by the University for its employees.

5. The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Committee of Selection appointed by the Governing Body for a term of 5 years from amongst the applicants responding to the advertisement of the University made for the purpose in all India Daily. Provided that the Committee of Selection shall have power to recommend the name of a suitable person who has not applied for appointment. Provided also that he / she shall in any case to hold the office on attaining the age of 65.

6. Duties and Powers of the Registrar

A. **Duties** - It shall be the duty of the Registrar:

i) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University, as the Governing Body shall commit to his charge.

ii) To issue all notice for convening the meetings of the Governing Body, The Board of Management, the Academic Council and other Authorities, Bodies and Committees declared by the Statutes and Authority of the University. He shall act as Secretary of all these Authorities, Bodies and Committees.

iii) To keep minutes of all the meetings of all the Authorities, Bodies and Committees and shall execute the decision taken by them.

iv) To conduct all official correspondence of the University.

v) To arrange for superintendent of the examinations of the University.

vi) To send to the Visitor and Chancellor

a) Copies of the agenda of the meeting of Governing Body, Board of Management and Academic council as soon as such agenda is issued.

b) The minutes of the meeting of the authorities mentioned in 6 A (vi) (a) above.

c) Such other papers and informations as the Visitor and Chancellor may direct him to supply.

vii) To collect the income, donations etc. and disburse the payment and maintain the accounts of the University through the Chief Finance and Accounts Officer of the University.

viii) To exercise all such powers as may be necessary or expedient to carry out the orders of the officers of the University and various authorities, bodies and committees.

ix) To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by Chancellor and Vice-Chancellor.

x) To perform such other duties as may from time to time, be entrusted to him by the Statutes, Ordinances, Regulations and Resolutions of Authorities and

xi) To render such assistance as may be desired by the Chancellor and Vice-Chancellor in the performance of his official duties.

B. Powers of the Registrar

i) Subject to the control of Governing Body the Registrar shall have powers to appoint class III and class IV employees of the University and shall exercise disciplinary control over them.

ii) The Registrar shall, if desired by the Chairman of any Authority, body or Committee, speak at its meeting.

STATUTE No.4

Terms and conditions of Appointment of Chief Finance and Accounts Officer his duties and powers

(Section 25 1 (c) read with section 17(1) of the Adhiniyam)

1. The Chief Finance and Accounts Officer shall receive salary in the pay scale prescribed by the State Government for University Finance officer / Deputy Registrar plus allowances admitted by the Governing Body from time to time.

2. No person shall be eligible for appointment as Chief Finance

and Accounts Officer unless he/she possesses the qualification laid down by the Governing Body for the post from time to time.

3. The Chief Finance and Accounts Officer shall be full time salaried officer of the University.

4. The Chief Finance and Accounts Officer shall be entitled to leave, leave salary, allowances and other benefits as may be prescribed by the University for its employees.

5. The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Selection Committee appointed by the Governing Body for a term of 5 years from amongst the applicants responding to the advertisement of the University made for the purpose in All India Daily. Also provided that the Selection Committee shall have the power to recommend the name of a suitable person who has not applied. Provide also that he/she shall cease to hold the office on attaining the age of 65.

6. Duties and Powers.

i) Subject to the control of Vice-Chancellor it shall be the duty of the Chief Finance and Accounts Officer:

a) To hold and manage the property and investments of the University including society and endowed property.
b) To ensure that the limits to be fixed by the Board of Management for recurring and non-recurring expenditure for the year are not exceeded and that entire money is spent for the purpose for which it is granted or allocated.
c) To keep a constant watch on the State of cash and bank balances and on the state of investments.

ii) Subject to the control of the Registrar, the Chief Finance and Accounts Officer shall -

a) Collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University.
b) Be responsible for the preparation of annual accounts and budget of the University.
c) To have the accounts of the University regularly audited.
d) Ensure that the registers of buildings, land, furniture, equipments, vehicles, etc. are maintained up-to-date and the stock checking is conducted in all offices and

institutions maintained by the University.

e) Suggest appropriate action against persons responsible for unauthorized expenditure and for other financial irregularities.

iii) The Chief Finance and Accounts Officer shall have the power to call from any office or institution of the University any information or returns that he may consider necessary for proper performance of his duties.

STATUTE No.5

Section 12 (1) to (5) of the Adhiniyam, the following shall be officers of the University namely:-

1) The Visitor (The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University)
2) The Chancellor
3) The Vice Chancellor
4) The Registrar
5) The Chief Finance and Accounts Officer

As mentioned in section 13 (1) to (3) of the Adhiniyam, The Visitor, his powers & duties namely:-

1) The Hon. Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University.

2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees & diplomas.

3) The visitor shall have the following powers namely,
   a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University.

   b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding of decision taken by any authority of the University is not conjoining with the Adhiniyam, Regulations, Ordinance or Rules, such directions as he may fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all the concerned.

Other Officers of the University

(Section 12(6) of the Adhiniyam)

1. In addition to the Officers mentioned in section 12(1) to (5) of the Adhiniyam below mentioned dignitaries shall be the officers of the University:

i) Deans/Directors
ii) University Librarian
iii) Director Physical Education
iv) Deputy Registrar
v) University Engineer/Estate Officer
vi) Assistant Registrars

2. The University may have one or more posts of any category mentioned above as per needs and approval by the Governing Body.

3. The Qualifications / eligibility for each officer shall be determined by the Governing Body.

4. These officers will be whole time salaried officers of the University.

5. The Officers shall draw salary as recommended by the University Grants Commission.

6. The Governing Body shall prescribe the qualifications and eligibility conditions for each category of officers and of appoint selection committee.

7. No person shall be appointed on these posts unless they possess the qualifications laid down for the respective post.

STATUTE No. 6

Terms and conditions of Appointment of Other Officers (Section 25(1) (d) of the Adhiniyam)

1. The University shall publish in All India daily the positions on which appointment has to be made along with the pay scales, qualifications and eligibility conditions.

2. On receipt of the application, the Governing Body shall appoint a selection Committee, which shall interview the candidates and prepare a panel merit list of suitable candidates. Provided that the Selection Committee can include the name of a person who is otherwise eligible even if he/ she has not applied.

3. The Governing Body shall make the appointment from the panel given by Selection committee.

4. The officer appointed shall execute an agreement and follow the rules and regulations of the University.

5. The officers shall be entitled to the leave, allowances and other benefits prescribed by the University for its employees from time to time.

6. The powers and duties of the Officers shall be such as the Governing Body may determine from time to time.

STATUTE No. 7

Conditions of service of University Employees (Section 25(1) (e) of the Adhiniyam)

Part-1 Definition and Applicability

1). Save as otherwise provided in the Adhiniyam and Statutes the provisions of this Statue shall apply to all the Employees of the University.

2) In this statute
   (a) "Pay" means the amount of monthly basic salary of the employees and shall not include any special or additional pay granted to him and any other emoluments, which he draws as allowances and largesses.
   (b) "Average pay" means the average monthly pay earned during the ten complete months immediately preceding the months in which the employee proceeds on leave or is suspended.
   (c) "Vacation post" means a post involving teaching duties and employees are entitled to winter and summer vacations.

Part - 2 Classification of post, appointment, terms and conditions.

3) The post in the University shall belong to the class and shall carry the scales of pay as given in appendix.
   (a) The Governing Body shall have the power to appoint the teachers and the officers of the University to whom salary is paid by the University.
   (b) Subject to the control of vice-Chancellor the Registrar shall have the power to appoint class III, class IV work charge and contingency paid staff of the University.
   (c) Save as otherwise provided in Statutes and the Ordinances the qualifications of the post in various categories shall be determined by the Governing Body

from time to time.

(d) The channel of promotion and percentage of the post to be filed by promotion shall be prescribed by the Governing Body from time to time. All promotions shall be made on the basis of seniority cum merit and performance appraisals.

4) Temporary appointment may be made to a temporary post or in leave vacancy in respect of permanent post.

5) The whole time University employee shall be at the disposal of University and he may be assigned duties in any manner required by the proper authority without claim of Additional remuneration.

6) The Board of Management may permit a University employee to perform a specified service for a private person body or Government and to receive remuneration thereof in form of fee, if it is satisfied that this can be done without detriment to his official duties or responsibilities.
Provided that half the amount of fees so received shall be credited to fund of the University.

7) The Head of the Branch, Department, Institute under whom the employee is working shall send to Registrar in form prescribed by the University, a confidential report, every year not later than 30th April, on the work and conduct of the employee of the preceding year ending on 31st March.

8) The confidential report and the opinion stating the employee fitness or otherwise for confirmation in service must be sent to the Registrar by the Head of Branch or Department or Institute, where the probationer is working at least one month before the date of expiry of the probation.

9) A temporary appointment may be terminated by either party without assigning any reason by giving to the other one-month notice or one month salary in lieu thereof. No such notice of payment of salary shall be necessary in case of termination of service or work charge or contingency paid employee.

10)

(a) If the appointing authority is not satisfied with and/ or conduct of the employee on probation his services may be terminated. In case of termination of the service of the employer on probation one month's notice shall be given to him or in lieu of notice he will be paid one months salary. The probationer may also terminate the

engagement by giving one month's notice or one month's salary.

(b) If the probationer is appointed by promotion and his work and conduct is not satisfactory the appointing authority may revert him to the post held by him before such promotion and such reversion shall not deemed to be a penalty.

(c) Every person appointed on permanent post under University by promotion or directs recruitment shall on

satisfactory completion of his period of probation shall be eligible for confirmation in the post.

11) On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on the post. A University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post acquires a lien on second post and ceases to hold any lien on the first one.

12) A permanent employee shall be required to give 3 month's notice in case he wishes to resign or he shall pay to University 3 month's salary in lieu of such notice. If the University terminates the services of a permanent employee a notice to that effect shall be served on him, 3 month's before the date on which he is to be relieved. In the absence of such notice the University shall pay him 3 month's salary. Such notice shall not be necessary if the employee is removed from the Service dismissed or compulsorily retired.

13) Before leaving the University service an employee, whether appointed temporarily or on probation or permanently shall hand over the charge of his post to the employee duly authorized to receive charge and shall return to the University all articles entrusted to him for his use and clear all dues outstanding against him.

14. University employee shall be entitled to leave, as per the leave rules framed by Board of Management and approved by the Governing Body.

Part 3 Suspension, Penalty and Disciplinary Authority:

15) The appointing authority may by an order place an employee, under suspension: -

(a) When disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending

Or

(b) On confirmation of a prima facie case against an employee on the charges of financial irregularities and/ or unethical activities detrimental to the interest of the University.

Or

(c) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority

(a) With effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours.

(b) With effect from the date of his conviction, if in the event of aconviction for an offence, he is sentenced to imprisonment and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to conviction.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made , shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the appointing authority .

(16) The services of a university employee may be terminated on anyof the following grounds.

(a) Willful neglect of duty

(b) Misconduct/ indiscipline

(c) Physical and mental unifitness

(d) On the abolition of Post held by him.

(e) Conviction by a court of law for an offence involving Moral turpitude.

(17) (1) The appointing authority may for good and sufficient reasons, impose on an employee the following penalties.

(a) Censure

(b) Recovery from his pay , whole or part of any pecuniaryloss caused to the university by negligence or breach of order by the employee.

(c) With holding the increments of pay.

(d) Reduction to lower time scale of pay, grade or post

(e) Compulsory retirement.

(f) Removal from Service

(g) Dismissal from service.

Besides above the penalty reasonable fine may be imposed on class IV employee for petty carelessness, unpunctuality etc.

(2) The appointing authority may institute the disciplinary proceding against the employe in accordance with the procedure laid down by the Governing body.

(18) Where the penalty is imposed by theRegistrar the employee may prefer an appeal to Vic-Chancellor within thirty days from the date on which order is served on the employee.

Part IV - Miscellaneous

19) Every employee shall at all times:
(a) Maintain absolute integrity
(b) Show devotion to duty; and
(c) Do nothing, which is unbecoming of an employee of the University.

20) No employee shall join or continue to be member of such association the objects and activities of which are prejudicial to the interest of the University or public order, decency or morality.

21) No employee shall-
i) participate in Public protests/ Dharanas/ Hartals/ demonstration prejudicial to the interest of University.
ii) resort to any violence
iii) participation, editing, management of any print or electronics media without prior sanction of the University
iv) divulge any matter of the University any where other than the competent authority
v) take any employment elsewhere either full time or part time without prior sanction form the University.

22) Any infringement of Para 19 to 21 of this Statute shall be regard as subversive of Good discipline and misconduct and will well justify the initiation of disciplinary action against such employee.

STATUTE No.8
Arbitration to resolve Disputes
(Section 25(1) (f) of the Adhiniyam)

1) In the event of dispute arising between the employee and the

employer, on the request of the employee the Vice-Chancellor shall appoint an Arbitrator not below the rank of District and Session Judge who shall listen to both the parties and pronounce his award.

2) The Board of Management shall consider the award and act as per directions of
the Arbitrator to resolve the Dispute.

3) If either of the parties i.e. employee or the employer is not satisfied with the award, they can approach the Chancellor to appoint a tribunal.

4) The tribunal shall consist of following members

i) A nominee of the Chancellor, not connected with the university, who will act as the Chairman.
ii) The nominee of the aggrieved employee and
iii) A nominee of the Board of Management

Provided that the aggrieved party shall approach the Chancellor within 30 days of the receipt of the award.

5) The decision taken by the tribunal shall be binding on both the parties.

STATUTE No. 9

Honorary Degree

(Section 25(1) (g) of the Adhiniyam)

1) A proposal for conferring of honorary degree shall be made by Academic Council.

2) The proposal shall be placed before a Committee consisting of the Vice Chancellor, a nominee of the Chancellor and a nominee of the Visitor.

3) If the Committee unanimously recommends that a honorary degree be conferred on the person on the ground that he is, in its opinion a fit and a proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before Governing Body.

4) The Chancellor shall send the proposal along with his own recommendation to the Visitor and on getting approval from the Visitor the person shall be conferred with the honorary degree either at the regular convocation or a special convocation held for the purpose.

STATUTE No. 10

Exemption from tuition fee and Award of Scholarship. (Section 25(1) (h) of the Adhiniyam)

1) The assistance obtained from the Central Government, State Government or any other authority, funding agency etc. towards meeting full or in part any amount towards fee otherwise payable by students belonging to socially disadvantaged or economically weaker sections shall be disbursed strictly as per directions of the authorities providing such assistances.

2) It shall be the duty of the Registrar and the Chief Finance and Accounts Officer of the University to ensure that the students get the stipend exactly as per the directions of the funding agency.

3) The University will also make provisions for awarding fellowships, scholarships and stipends from its own sources. The terms and conditions of the award shall be laid down in the ordinance made under section 27 (1) (d) of the Adhiniyam.

STATUTE No. 11

Policy of Admission including Reservation of seats (Section 25(1) (i) of the Adhiniyam)

1) The admission to various courses shall be made exactly in order of merit made on the basis of the marks obtained at the qualifying examination.
Provided that in the courses the University decides to admit the students on the basis of the entrance test held either by the University or by any body/ agency on behalf of the University the admission shall be granted on the basis of merit secured at the entrance examination.

2) The reservation of seats at each institution/ center in each course of study shall be as per rules £Tamed for the reservation of seats for SC/ ST/OBC and other categories by the Government of Chattisgarh from time to time.
Provided that if seat of any reserve category remains vacant due to non availability of the eligible candidates in that category it shall be filled up in the following order:

SC → ST → OBC → OTHERS → GENERAL

Provided also that the candidates admitted under reserved

category shall be required to pay the fees as decided by the University for course and that the paid vacant seats must be filled before the start of the Academic session.

3) The Chancellor shall have the power to grant at least one admission to each course subject to a maximum of 2% of the total seats available in that course.
Provided that the admission shall be accorded only to those candidates who are eligible to be admitted to that course.

STATUTE No. 12

Provisions Regarding Fee to be charged form the students
(Section 25(1) (j) of the Adhiniyam)

1. The fee for each course of study shall be calculated for each student on the basis of total expenditure on the course and the seats earmarked for the course. This fee shall be charged as course fee (tuition and laboratory fee).

2. Each student shall also be charged enrolment fee, Development fee, examination fee, etc. as provided in Regulations.

STATUTE No. 13

Provisions Regarding Number of Seats in Each Course
(Section 25(1) (k) of the Adhiniyam)

1. In each graduate course the maximum number of students admitted shall be 30 at the University teaching department and at its different centres. The University shall, however, decide the number of students to be admitted at a center on evaluating its infrastructure facilities and strength of faculties. In no case the number shall exceed 30 for a particular course at particular center.

2. At the graduate degree level each section of the class shall have a maximum strength of 60 students.
The number of sections which can be allowed at a particular center shall be adjudged on the basis of the infrastructural facilities available at the centre and the faculty strength.

3. The Academic Council shall lay down the norms having details regarding the Infrastructural facilities and required faculty strength for each course and place it before the Board of Management for approval. After it's, it shall be strictly followed for deciding the seats in each course at each centre.

STATUTE No. 14

Academic Council
(Section 9(1) (3) of the Adhiniyam)

1. (a) The Academic Council shall consist of following members:
   (i) Vice- Chancellor - Chairman
   (ii) Deans of faculties of the University
   (iii) Chairman Board of Studies
   (iv) Professors of the University
   (v) Five teachers of centres nominated by the Vice Chancellor in rotation by seniority.
   (vi) Two lecturers of the university nominated by the ViceChancellor in rotation by seniority.
   (vii) Registrar

   (b) One third of total members of Secretary Academic Council shall from the Quorum.
   Provided at no quorum shall be necessary for adjured meetings.

   (c) The academic Council shall have the power to co-opt as members having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business, which may come before the council for consideration. The member so co-opted shall have all the rights of the members of the council.

   (d) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred in sub-para (c) shall hold the office for a term of three years.

2. The Academic Council shall have following powers and perform following duties:

   (i) To exercise general supervision over the academic policies of the University and to provide directions for methods of instructions, cooperative teaching for the improvement of academic standards.
   (ii) To consider matters of general academic interest and to take appropriate action in this regard.
   (iii) To assign departments to the faculties and members to the faculties;
   (iv) To make proposals for the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award.
   (v) To nominate its own to consider the proposal for establishment of centre for establishment of centres of the University.

(vi) To Prescribe qualifications for recognition of persons as tachers of the University and to accord such recongnition

(vii) To make arrangements for the conduct of examination and arrange for the publication of the results.

(viii) To prescribe the qualfications for the award of Certificates, Diplomas and Degree.

(ix) To recognize eminet persons of any subject as Honourary professor and to guide research in that subject.

3. The Academic Council may appoint a standing Committee consisting of:

(i) vice-Chancellor - Chairman.

(ii) 3 of its members as members and

(iii) Registrar Secretary.

4. The "Standing Committee" shallhave following Powers and shall perform following duties.

(i) The meeting of the Committee shall be concerned under the direction of Vice-Chancellor.

(ii) It shall render advice on the equivalence of examinations in consultation with the faculty, concerned.

(iii) It can dispose off anymatter of academic council and report it at the next meeting of Academic Council.

(iv) Standing Committee may invite such persons who can render fruitful advice on the matter under consideration.

Raipur, the 23rd September 2003

No. F-73-194/H E/38/03.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "VIVEKANANDA NATIONAL UNIVERSITY, RAIGARH" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "VIVEKANANDA NATIONAL UNIVERSITY, RAIGARH" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. C. SINHA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-179/उ. शि./2003/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "स्वराज यूनिवर्सिटी" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में रहेगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "स्वराज यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd September 2003

No. F-73-179/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "SWARAJ UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "SWARAJ UNIVERSITY" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73/164/उ. शि./2003/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नालॉजी यूनिवर्सिटी'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में रहेगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नालॉजी यूनिवर्सिटी'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd September 2003

No. F-73/164/ H E/2003/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY UNIVERSITY" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-73-148/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd October 2003

No. F-73-148/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "UNIVERSITY OF MEDIA ARTS, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "UNIVERSITY OF MEDIA ARTS, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व, विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	तमनार प. ह. नं. 38	107.356	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक 42/भू-अर्जन/01/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	हाटकोंदल	39.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	जयरामपारा तालाब के डुब में आने वाली भूमि.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एम. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक 692/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धिकुड़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	28	0.84
योग	1	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोठिया पिकअप वियर बांध एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जनवरी 2004

क्रमांक 693/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोटिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.91 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	264/1	1.18
	268/1	0.70
	189	0.50
	253/1	0.14
	268/2	0.30
	216/1	0.54
	215	1.56
	214	0.77
	212	0.17
	211	0.14
	178	1.03
	279	0.25
	274	0.45
	264/1	0.18
योग	14	7.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोठिया पिकअप वियर बांध एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 दिसम्बर 2003

क्रमांक 748/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-60.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/1	1.18
90/1	1.58
92/1	0.35
100/1	3.20
96/1	0.64
780	0.18
783	0.50
790	5.22
787	0.25
789/1	9.06
99	3.48
89/2	2.30
90/2	5.46
92/2	0.43
93/3	0.04
98	1.30
781/1	2.70
784	0.71
103/1	3.70
792	1.92
799	0.24
103/2	1.97
100/2	1.84
92/3	0.96
94/4	0.14
94/5	0.22
102	0.08
782	8.52
785	0.36
797	1.58
800	0.22
योग	60.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-हरदी भिभौंरी जलाशय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन अधिकारी) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 दिसम्बर 2003

क्रमांक 749/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
581	0.68

	(1)	(2)
	584	1.00
	582	0.28
	585/1	0.36
	583	0.66
	585/2	0.38
योग	6	3.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-हरदी भिभौंरी जलाशय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्र. क्र . 05/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-घरघोड़ा
 (ग) नगर/ग्राम-उजलपुर, प. ह. नं. 36
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.710 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	101	6.710
योग		6.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 12-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम
 (ख) तहसील-कवर्धा
 (ग) नगर/ग्राम-लखनपुर, प. ह. नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
568/1	0.03

(1)	(2)
568/2	0.22
569/1	0.40
569/2	0.02
570/2	0.06
570/4	0.07
570/5	0.07
योग	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रबेली से लखनपुर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 13-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
56/1	0.02
60/1	0.02
60/5-6	0.02
60/7	0.02
67/3	0.03
67/5	0.01
67/6	0.01
60/4	0.02
67/1	0.02
88/1	0.08
67/2	0.01
योग	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से गोछिया तक निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 14-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमो, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
98/1	0.07
108	0.04
111	0.01
113/2	0.02
115/3	0.02

(1)	(2)
142/1	0.02
142/2	0.02
144/1	0.03
144/3	0.05
144/5	0.04
145/1	0.03
158/2	0.02
158/2	0.02
158/6	0.10
159	0.02
163/1	0.06
163/92	0.03
163/13-14	0.03
योग	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से गोछिया तक सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 15-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर कला, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
359	0.41
360	0.03
361	0.06
363	0.02
योग	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रवेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 16-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-रवेली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
759/4	0.23
789	0.01
781/1	0.44
787/2	0.01
783	0.04

(1)	(2)
782/1	0.02
795/3	0.05
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रवेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 17-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-सूखाताल, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
327	0.02
326	0.02
325	0.01
939	0.10
938/2	0.08
935	0.09
934	0.18
933	0.09
932/2	0.11
929	0.12
926/2	0.40
947/1	0.08
947/2	0.08
948/3	0.18
949/3	0.36
योग	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 18-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-रबेली, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
755/4	0.04
795/2	0.16
795/5	0.05
797	0.10
806	0.14

(1)	(2)
807/3	0.16
771	0.07
772/5	0.15
7.72/3	0.16
772/8	0.08
772/2	0.10
योग	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता हैं.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 19-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-छिरहा, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
223/3	0.02
260/2	0.01
260/1	0.01
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से गोछिया तक सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 21-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
144/2	0.10
146/1	0.05
146/2	0.05
योग	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक़ता है-पोड़ी से बैहरसरी सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 22-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-उसलापुर, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
8/1	0.08
31/1	0.02
8/2	0.07
9/2	0.18
9/8	0.02
150/1	0.07
25	0.07
155/1-2	0.05
32/2	0.02
32/1	0.02
29/2	0.02
159/2	0.18
157/3	0.08
11/2	0.09
4/2	0.07
5/1-2	0.25
8/3	0.10
156/2	0.05
9/7	0.02
23	0.02
151/2	0.03
167/3	0.07
167/1	0.07
30	0.01
26/3	0.02
157/2	0.15
156/1	0.05
160/1	0.21
7/2	0.27
9/5	0.02
9/6	0.02
22, 54, 55, 56 (4)	0.04
169/1	0.10
158/2	0.07
31/2	0.02
168/2	0.10
29/1	0.01
21	0.02
157/1	0.09
11/3	0.06
योग	2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पोड़ी से बैहरसरी सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 23-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-नेवारी, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
134/2	0.36
133/6	0.01
133/8	0.01
135/5	0.32
141/4	0.12
141/2	0.12
147/1	0.11
147/2	0.19
147/3	0.01
147/4	0.05
153/1	0.49
201/2	0.04
203	0.05
योग	1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 24-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-डबराभाठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
221	0.08
222/1	0.01
222/2	0.01
223/1	0.02
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 25-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बिजई, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
31/2	0.08
30	0.06
29/2	0.04
29/1	0.06
114/1	0.04

(1)	(2)
114/2	0.04
127/1	0.02
128/2	0.08
129/2	0.07
योग	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोराताल से खेली सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 26-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
956	0.15
959	0.20
160/1	0.14
962	0.15
963	0.01
970/3	0.07
970/2	0.14
977/2	0.08
978/1	0.09
978/2	0.09
466	0.04
781	0.06
462	0.04
410/3	0.01
312/3	0.01
419/3	0.02
420/2	0.02
423/4	0.03
423/3	0.03
424	0.02
431	0.03
योग	1.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चारभाठा से गोछिया सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 27-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-जोराताल, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
222	0.02
223	0.02
228	0.01
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

प्र. क्र. 28-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बंदौरा ,प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
401/1	0.004
401/2	0.004
403/3	0.012
405	0.004
406	0.004
407	0.004
404/1	0.004
404/2	0.004
109/1	0.008
409/3	0.008
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुख्य मार्ग से गोछिया सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2004

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 05 अ/82, वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पंधी, प. ह. नं. 148/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
306	0.14

(1)	(2)
307	0.12
308	0.11
311	0.39
309	0.11
325	0.05
323	0.12
501	0.12
428	0.17
431	0.20
432	0.12
538	0.59
430	0.04
433	0.22
440	1.97
434	0.21
435	0.20
438	0.35
441	0.24
442/1	0.04
442/2	0.11
445	0.36
433	0.23
444	0.27
446	0.10
447/2	0.16
448	0.12
504	0.41
505	0.24
507	0.25
508	0.35
320	0.55
491	2.93
492	0.40
498	3.44
500	0.51
502	0.19
503	0.20
506	0.68
509	0.18
510	0.29
511	0.04
512	0.20
513	0.55
514	0.21
515	0.06
522	0.06
516	0.18
517	0.09
326	0.30
536	0.47
537	0.40
539	0.10
540	0.10
542	0.26
543	0.29
544	0.24
545	0.15
548	0.12
546	0.02
499	2.12
523	0.19
532	0.02
490	0.05
454	0.13
449	0.29
427	0.01
429	0.11
312	0.12
322	0.16
321	0.27
310	0.12
योग 72	24.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2004

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 04 अ/82, वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-निसदा, प. ह. नं. 148/44

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
447	0.37
448	0.50
449	0.30
452	0.42
450	0.58
451	0.47
453	0.39
1305	0.09
454	0.33
455	0.58
1311/2	0.49
456	0.18
539	0.10
540	0.20
542	0.50
541	0.39
543	0.52
544	1.56
552	0.08
545	0.37
554	0.53
546	0.99
547	0.46
553	0.97
555	0.46
556	1.20
931	0.50
930	0.50
538	0.09
933	0.25
932	0.33
557	0.07
1300	0.11
1306	0.05
1301	0.21
1303	0.13
1302	0.35
1304	0.22
1307	0.07
1310	0.04
1311/1	0.53
1297	0.03
1314/1	0.15
1314/2	0.10
1315	0.21
1316	0.21
1317	0.11
1325	0.13
1320	0.01
1312	0.06
योग 50	17.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.